Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

28 SEPT - 4 OCTOBER

1ST WEEK OF OCTOBER

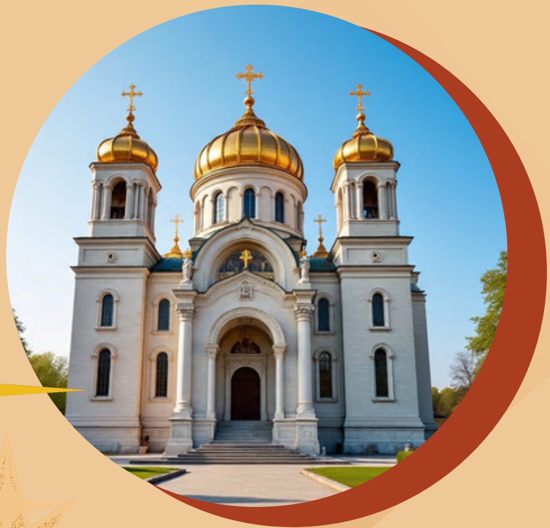

35+ MCQ with detailed explanation

- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement

Ques: Hero Future Energies secured ₹1,024 crore funding from SBI for a hybrid project in which state?
हीरो फ्यूचर एनर्जीज़ ने हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए SBI से ₹1,024 करोड़ की फंडिंग किस राज्य में प्राप्त की?

A. Rajasthan / राजस्थान
B. Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
C. Gujarat / गुजरात
D. Tamil Nadu / तमिलनाडु
E. Karnataka / कर्नाटक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Hero Future Energies (HFE), the renewable energy arm of Hero Group, secured ₹1,024 crore funding from SBI for a 60 MW Hybrid Peak Power Project in Kurnool district, Andhra Pradesh.
- हीरो ग्रुप की नवीकरणीय ऊर्जा शाखा, HFE ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में 60 मेगावाट हाइब्रिड पीक पावर प्रोजेक्ट के लिए SBI से ₹1,024 करोड़ की फंडिंग हासिल की।
- The project combines solar, wind, and storage technologies and is contracted with Solar Energy Corporation of India (SECI).
- यह परियोजना सौर, पवन और स्टोरेज तकनीकों को जोड़ती है और इसे SECI से अनुबंधित किया गया है।
- Financing is structured through SPV – Clean Solar Power Barmer, with repayment spread over 21 years to ensure timely completion.
- फंडिंग विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) – क्लीन सोलर पावर बाड़मेर के माध्यम से संरचित है, और चुकौती 21 वर्षों में फैली होगी, जिससे समय पर परियोजना पूरी हो सकेगी।
- HFE is backed by global investors like IFC and KKR, strengthening India's renewable energy infrastructure and supporting long-term energy security.
- HFE को IFC और KKR जैसे वैश्विक निवेशकों का समर्थन प्राप्त है, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है।

Ques: Who has been appointed as the new CFO of IndusInd Bank?
इंडसइंड बैंक के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A. Viral Damania / वायरल दमानीया
B. Santosh Kumar / संतोष कुमार
C. Gobind Jain / गोबिंद जैन
D. Sunil Mehta / सुनील मेहता
E. Rakesh Sharma / राकेश शर्मा

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Viral Damania has been appointed as the new Chief Financial Officer (CFO) of IndusInd Bank.
- वायरल दमानीया को इंडसइंड बैंक का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) नियुक्त किया गया है।
- He brings over 27 years of experience, having earlier served as the CFO of Bank of America India.
- उनके पास 27 वर्षों का अनुभव है और वे पहले बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के CFO थे।
- With this appointment, the additional responsibilities of Santosh Kumar as Special Officer-Finance & Accounts cease immediately, though he will continue as Deputy CFO.
- इस नियुक्ति के साथ ही संतोष कुमार की विशेष अधिकारी- वित्त एवं लेखा की अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ तत्काल समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वे उप CFO के रूप में बने रहेंगे।
- The former CFO Gobind Jain had resigned earlier this year citing personal reasons.
- पूर्व CFO गोबिंद जैन ने इस वर्ष की शुरुआत में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया था।

Ques: What is the objective of the BOI Trade Easy digital platform launched by Bank of India for MSMEs?
BOI ट्रेड ईज़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, जो बैंक ऑफ इंडिया द्वारा MSME के लिए लॉन्च किया गया है?

A. To provide long-term loans to large corporations / बड़ी कंपनियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना
B. To disburse Rs.1,000 crore in working capital loans to MSMEs within 4–6 months / MSME को अगले 4–6 महीनों में 1,000 करोड़ रुपये का वर्किंग कैपिटल ऋण वितरित करना
C. To offer free financial advisory services to startups / स्टार्टअप को मुफ्त वित्तीय सलाह सेवाएँ प्रदान करना
D. To provide grants for MSME infrastructure development / MSME अवसंरचना विकास के लिए अनुदान प्रदान करना
E. To invest in foreign markets for MSME growth / MSME विकास के लिए विदेशी बाजारों में निवेश करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- BOI Trade Easy is a digital credit platform launched by Bank of India in partnership with Cashinvoice, aimed at providing instant working capital loans to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) within 30 minutes of application.
- BOI ट्रेड ईज़ी एक डिजिटल क्रेडिट प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे बैंक ऑफ इंडिया ने Cashinvoice के साथ मिलकर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य MSME को आवेदन के 30 मिनट में तुरंत वर्किंग कैपिटल ऋण प्रदान करना है।
- The objective is to disburse Rs.1,000 crore in working capital loans within the next four to six months, reaching over 200,000 MSMEs nationwide.
- इसका उद्देश्य अगले 4–6 महीनों में 1,000 करोड़ रुपये के वर्किंग कैपिटल ऋण वितरित करना है, जिससे देशभर में 200,000+ MSME तक पहुंच बनाई जा सके।

Ques: Which two institutions launched the Quick Response-based Unified Payments Interface (UPI) for Indian travelers in Qatar?
कतर में भारतीय यात्रियों के लिए **Quick Response** आधारित **Unified Payments Interface (UPI)** को लॉन्च करने वाली दो संस्थाएँ कौन सी हैं?

A. NPCI International Payments Limited & Qatar National Bank / एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और कतार नेशनल बैंक
B. Reserve Bank of India & State Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक
C. Paytm & Qatar National Bank / पेटीएम और कतार नेशनल बैंक
D. NPCI International Payments Limited & Emirates NBD / एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और एमिरेट्स एनबीडी
E. Visa & Mastercard / वीज़ा और मास्टरकार्ड

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

• On February 25, 2025, NPCI International Payments Limited (NIPL) and Qatar National Bank (QNB) launched the Quick Response-based UPI for Indian travelers in Qatar.
• 25 फरवरी 2025 को, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड)NIPL) और कतार नेशनल बैंक)QNB) ने कतर में भारतीय यात्रियों के लिए Quick Response आधारित UPI लॉन्च किया।
• The UPI service was first made live for merchants at Qatar Duty Free, Hamad International Airport, Doha.
• इस UPI सेवा को सबसे पहले कतर ड्यूटी फ्री, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोहा में व्यापारियों के लिए लाइव किया गया।
• Qatar became the 8th country to integrate UPI after Bhutan, France, Mauritius, Nepal, Singapore, Sri Lanka, and the UAE.
• भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई के बाद कतर UPI को एकीकृत करने वाला 8वां देश बन गया।
• QNB is the first bank in Qatar to enable UPI acceptance, with payments processed at POS terminals powered by Japanese payment aggregator NETSTARS.
• QNB कतर का पहला बैंक बन गया जिसने UPI स्वीकार्यता सक्षम की, और भुगतान POS टर्मिनलों पर NETSTARS द्वारा समर्थित किया जाता है।

Ques : Recently, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) increased its stake in Yes Bank to what percentage?
प्रश्न) हाल ही में सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन :SMBC) ने यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाई?

A. 20%
B. 22%
C. 24.22%
D. 26%
E. 23%

Answer : Option C

Explanation | व्याख्या:

• Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) of Japan acquired an additional 4.22% stake in Yes Bank, raising its shareholding from 20% to 24.22%.
• जापान की SMBC ने यस बैंक में 4.22% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी, जिससे उसकी हिस्सेदारी 20% से बढ़कर 24.22% हो गई।
• SMBC bought 132.39 crore shares through an off-market sale on 22nd September.
• SMBC ने 22 सितंबर को 132.39 करोड़ शेयर ऑफमार्केट सेल के जरिए खरीदे।-
• After this acquisition, SMBC's total holding in Yes Bank reached 759.51 crore shares.
• इसके बाद, यस बैंक में SMBC की कुल हिस्सेदारी 759.51 करोड़ शेयर हो गई।

Exam Genius

Ques: From when will the RBI's "Authentication Mechanisms for Digital Payment Transactions" Directions, 2025, come into force, mandating two-factor authentication for all digital payments in India?
भारत में सभी डिजिटल भुगतानों के लिए two-factor authentication को अनिवार्य करने वाले RBI के "Authentication Mechanisms for Digital Payment Transactions" Directions, 2025, कब से लागू होंगे?

A. 1 April 2025
B. 1 April 2026

C. 1 October 2025
D. 1 October 2026
E. 1 January 2026

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• The RBI has finalized the “Authentication Mechanisms for Digital Payment Transactions” Directions, 2025, which will come into force from 1 April 2026.
• RBI ने “Authentication Mechanisms for Digital Payment Transactions” Directions, 2025 को अंतिम रूप दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
• Under these guidelines, all digital payments in India must satisfy two-factor authentication (2FA).
• इन दिशानिर्देशों के तहत, भारत में सभी डिजिटल भुगतानों के लिए दोचरणीय -) प्रमाणीकरण2FA) आवश्यक होगा।
• At least one authentication factor must be dynamic, i.e., unique or changing for each transaction (e.g., OTP).
• कम से कम एक प्रमाणीकरण कारक गतिशील होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक लेनदेन के लिए अद्वितीय या बदलता हुआ जैसे), OTP)।
• For non-recurring, cross-border card-not-present transactions, issuers must validate the Additional Factor of Authentication (AFA) when requested by overseas merchants, to be implemented by 1 October 2026.
• गैरआवर्ती-, अंतर्राष्ट्रीय कार्डलिए प्रेजेंट लेनदेन के-नॉट-, कार्ड जारीकर्ता को विदेशी व्यापारी द्वारा अनुरोध पर Additional Factor of Authentication (AFA) को मान्य करना होगा, जिसे 1 अक्टूबर 2026 तक लागू करना अनिवार्य है।

Ques: What is the Government of India's projected gross market borrowing for FY26?
वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत सरकार का सकल बाजार उधार कितना है?

A. ₹13.50 lakh crore
B. ₹14.01 lakh crore
C. ₹14.82 lakh crore
D. ₹15.00 lakh crore
E. ₹16.20 lakh crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Government of India announced gross bond issuance of ₹14.82 lakh crore for FY26, which will remain unchanged for the second half of the year.
- भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹14.82 लाख करोड़ का सकल बॉन्ड जारी करने की घोषणा की, जो वर्ष की दूसरी छमाही में अपरिवर्तित रहेगा।
- Of this, ₹8 lakh crore is planned for the first half (April–September 2025) and ₹6.82 lakh crore for the second half (October–March 2026).
- इसमें से ₹8 लाख करोड़ पहली छमाही (अप्रैल–सितंबर 2025) और ₹6.82 लाख करोड़ दूसरी छमाही (अक्टूबर–मार्च 2026) के लिए निर्धारित है।
- In comparison, gross borrowing in FY25 was ₹14.01 lakh crore.
- तुलना के लिए, वित्त वर्ष 2025 में सकल उधारी ₹14.01 लाख करोड़ थी।
- The fiscal deficit projection for FY26 has been set at 4.4% of GDP.
- वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान GDP का 4.4% रखा गया है।

Ques: Which institution reaffirmed its dedication to global best practices in the foreign exchange market by renewing its Statement of Commitment to the FX Global Code?
विदेशी मुद्रा बाजार में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, किस संस्था ने FX Global Code के लिए अपनी Statement of Commitment नवीनीकृत की?

A. Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
B. Securities and Exchange Board of India / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
C. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
D. International Monetary Fund / अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
E. State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

• On September 2025, the Reserve Bank of India renewed its Statement of Commitment (SoC) to the FX Global Code, reaffirming its adherence to global best practices in the foreign exchange market.
• सितंबर 2025 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने FX Global Code के लिए अपनी Statement of Commitment (SoC) को नवीनीकृत किया, और विदेशी मुद्रा बाजार में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
• As per the SoC, RBI acts as a Market Participant as defined by the Code and is committed to conducting its FX market activities according to the Code's principles.
• SoC के अनुसार, RBI कोड द्वारा परिभाषित Market Participant के रूप में कार्य करता है और अपने FX बाजार गतिविधियों को कोड के सिद्धांतों के अनुसार संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
• The FX Global Code is a set of international principles of good practice, first published in 2017 under a strategic partnership between central banks and market participants worldwide.
• FX Global Code अच्छे अभ्यास के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का एक समूह है, जिसे 2017 में विश्व के केंद्रीय बैंकों और बाजार प्रतिभागियों के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत पहली बार प्रकाशित किया गया था।
• The Global Foreign Exchange Committee (GFXC), responsible for promotion and maintenance of the Code, reviewed it for the first time in July 2021 and later in December 2024.
• Global Foreign Exchange Committee (GFXC), जो कोड के प्रचार और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, ने इसे पहली बार जुलाई 2021 और बाद में दिसंबर 2024 में समीक्षा किया।

EXAM Genius

Ques : According to OECD, what is India's FY26 growth forecast?
OECD के अनुसार, भारत की FY26 विकास दर का अनुमान कितना है?

A. 6.2%
B. 6.3%
C. 6.5%
D. 6.7%
E. 7.0%

Answer :Option D

Explanation | व्याख्या:

• The OECD revised India's FY26 GDP growth forecast upward from 6.3% to 6.7%, citing GST reforms, fiscal easing, and strong domestic demand.
• OECD ने भारत की FY26 GDP वृद्धि दर को 6.3% से बढ़ाकर 6.7% किया है। इसके पीछे जीएसटी सुधार, राजकोषीय रियायत और मजबूत घरेलू मांग मुख्य कारण हैं।
• It also highlighted risks from higher tariffs and potential pressure on the export sector.
• OECD ने उच्च टैरिफ दरों और निर्यात क्षेत्र पर संभावित दबाव को भी जोखिम के रूप में बताया।
• Global agencies like S&P Global, IMF, and World Bank kept their FY26 growth forecasts largely unchanged at 6.5%, 6.2%, and 6.3%, respectively.
• वैश्विक एजेंसियों जैसे S&P Global, IMF और विश्व बैंक ने अपनी FY26 वृद्धि दर के अनुमान क्रमशः 6.5%, 6.2%, और 6.3% पर बरकरार रखे।

Ques: Which regulator increased the minimum net worth requirement for custodians from Rs 50 crore to Rs 75 crore in 2025?
किस नियामक ने 2025 में कस्टोडियंस के लिए न्यूनतम नेट वर्थ आवश्यकता को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये किया?

A. Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
B. Securities and Exchange Board of India / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
C. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
D. National Stock Exchange / राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज
E. State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• In 2025, SEBI raised the minimum net worth requirement for custodians from Rs 50 crore to Rs 75 crore by amending the SEBI (Custodian) Regulations, 1996.
• 2025 में, SEBI ने SEBI (Custodian) Regulations, 1996 में संशोधन करके कस्टोडियंस

के लिए न्यूनतम नेट वर्थ आवश्यकता को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये किया।

• Following this amendment, the regulations are now called 'SEBI (Custodian) (Amendment) Regulations, 2025'.

• इस संशोधन के बाद, इन नियमों को अब 'SEBI (Custodian) (Amendment) Regulations, 2025' कहा जाता है।

• The new provisions will come into force six months from the date of their publication in the official gazette.

• नई व्यवस्था आधिकारिक गज़ट में प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद लागू होगी।

• Existing custodians are required to meet the new capital adequacy requirement within three years of the commencement of the new regulations.

• वर्तमान कस्टोडियंस को नई नियमावली की शुरुआत की तारीख से तीन वर्षों के भीतर नई पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को पूरा करना होगा।

• SEBI also extended the implementation dates for phase-II and phase-III of the framework to August 08, 2025, and December 15, 2025, respectively.

• SEBI ने इस ढांचे के phase-II और phase-III के कार्यान्वयन की तारीखों को क्रमशः 08 अगस्त 2025 और 15 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया।

Ques: Who has been appointed as the Chairman of Piramal Finance following the recent merger of Piramal Enterprises?
हाल ही में Piramal Enterprises के विलय के बाद Piramal Finance के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A. Anand Piramal / आनंद पिरामल
B. Ajay Piramal / अजय पिरामल
C. Jairam Sridharan / जैराम श्रीधरन
D. Shikha Sharma / शिखा शर्मा
E. Uday Kotak / उदय कोटक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

• Anand Piramal has been appointed as the Chairman of Piramal Finance, replacing his father, Ajay Piramal, following the recent merger of Piramal Enterprises.

• हाल ही में Piramal Enterprises के विलय के बाद, आनंद पिरामल को Piramal Finance का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिन्होंने अपने पिता अजय पिरामल की जगह ली।
• Jairam Sridharan has been appointed as the MD & CEO of Piramal Finance.
• जैराम श्रीधरन को Piramal Finance का MD और CEO नियुक्त किया गया है।
• Shikha Sharma, former MD & CEO of Axis Bank, has been appointed as a Non-Executive Director of Piramal Finance.
• अक्षय बैंक की पूर्व MD और CEO शिखा शर्मा को Piramal Finance का Non-Executive Director नियुक्त किया गया है।

Ques: Which organization has directed banks to settle unclaimed deposits through special camps between October and December 2025?
किस संगठन ने बैंकों को अवितरित जमा राशि के निपटारे के लिए अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है?

A. SEBI / सेबी
B. IRDAI / आईआरडीएआई
C. RBI / आरबीआई
D. Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
E. NABARD / नाबार्ड

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has asked all banks to settle unclaimed deposits such as savings/current accounts inactive for 10 years, term deposits not claimed within 10 years, dividends, interest warrants, pensions, etc., over the next three months (October–December 2025).
- भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अगले तीन महीनों अक्टूबर)–दिसंबर 2025) में अवितरित जमा राशि जैसे 10 वर्षों से निष्क्रिय बचतचालू खाते/, परिपक्वता के बाद 10 वर्षों तक न निकाले गए सावधि जमा, डिविडेंड, ब्याज वारंट, पेंशन आदि का निपटारा करें।
- Such deposits are transferred to the Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) maintained by RBI, but claimants can withdraw them later

with interest.

- इस प्रकार की राशि RBI द्वारा बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष)DEAF) में स्थानांतरित की जाती है, लेकिन जमाकर्ता बाद में ब्याज सहित इसे निकाल सकते हैं।
- To facilitate settlement, RBI will organize district-level week-long joint camps, starting in Gujarat in October 2025 and continuing across India until December.
- निपटारे को सुगम बनाने के लिए RBI जिलास्तरीय सप्ताहभर के संयुक्त शिविर - आयोजित करेगा; पहला शिविर अक्टूबर 2025 में गुजरात में होगा और दिसंबर तक देशभर में आयोजित होंगे।
- The State Level Bankers' Committee (SLBC) will lead the initiative in respective states to ensure maximum claim settlements.
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)SLBC) राज्यों में इस पहल का नेतृत्व करेगी और अधिकतम निपटारा सुनिश्चित करेगी।

Ques: What is the Ways and Means Advances (WMA) limit set by the RBI for the second half of FY 2025-26 (October 2025–March 2026)?
RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही अक्टूबर)2025–मार्च 2026) के लिए Ways and Means Advances (WMA) की सीमा कितनी तय की है?

A. ₹25,000 crore
B. ₹50,000 crore
C. ₹75,000 crore
D. ₹1,00,000 crore
E. ₹1,50,000 crore

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI), in consultation with the Government of India, set the WMA limit for H2 FY 2025-26 (Oct–Mar 2026) at ₹50,000 crore.
- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया)RBI) ने भारत सरकार के परामर्श से FY 2025-26 की दूसरी छमाही अक्टूबर)–मार्च 2026) के लिए WMA सीमा ₹50,000 करोड़ तय की है।
- RBI may trigger fresh market loan floatation once the Government

utilises 75% of this limit.

- जब सरकार इस सीमा का 75% उपयोग कर लेगी, तब RBI नया बाजार ऋण जारी कर सकता है।
- For the first half (H1) of FY 2025-26, the WMA limit was ₹1,50,000 crore.
- वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही)H1) के लिए सीमा ₹1,50,000 करोड़ थी।
- Interest rate: WMA = Repo Rate; Overdraft = Repo Rate + 2%.
- ब्याज दर: WMA = रेपो रेट; ओवरड्राफ्ट + रेपो रेट =2%।

Ques: What is the minimum net worth requirement for an SRO in the Fintech (SRO-FT) sector?
फिनटेक)SRO-FT) क्षेत्र में एक SRO के लिए न्यूनतम नेट वर्थ आवश्यकता क्या है?

A. ₹1 crore
B. ₹2 crore
C. ₹5 crore
D. ₹10 crore
E. ₹15 crore

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Fintech Association for Consumer Empowerment (FACE) is India's first Self-Regulatory Organisation for Fintech (SRO-FT).
- फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट)FACE) भारत का पहला स्व-) नियामक संगठनSRO-FT) है।
- To qualify as an SRO-FT, an entity must have a minimum net worth of ₹2 crore.
- एक SRO-FT बनने के लिए न्यूनतम नेट वर्थ ₹2 करोड़ होना आवश्यक है।
- In comparison, general financial market SROs like FIMMDA require ₹10 crore, while SROs within the Account Aggregator (AA) ecosystem also need ₹2 crore.
- तुलना के लिए, सामान्य वित्तीय बाजार SRO जैसे FIMMDA के लिए ₹10 करोड़ आवश्यक हैं, जबकि AA इकोसिस्टम के SROs के लिए भी न्यूनतम ₹2 करोड़ है।
- After RBI recognition, FACE's membership grew from 60 in August 2024 to 275 in August 2025, showing its expanding role in fintech regulation

and consumer empowerment.

- आरबीआई मान्यता के बाद, FACE की सदस्यता अगस्त 2024 में 60 से बढ़कर अगस्त 2025 में 275 हो गई, जो भारत में फिनटेक विनियमन और उपभोक्ता सशक्तिकरण में इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

Ques: SBI Mutual Fund recently launched its first scheme under the Specialised Investment Fund (SIF) category. What is its name?
SBI म्यूचुअल फंड ने हाल ही में स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड)SIF) श्रेणी के तहत अपनी पहली योजना लॉन्च की। इसका नाम क्या है?

A. SBI Magnum Balanced Fund / SBI मैग्नम बैलेंस्ड फंड
B. SBI Magnum Equity Hybrid Fund / SBI मैग्नम इक्विटी हाइब्रिड फंड
C. SBI Magnum Hybrid Long Short / SBI मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट
D. SBI Magnum Debt Fund / SBI मैग्नम डेट फंड
E. SBI Magnum Arbitrage Fund / SBI मैग्नम आर्बिट्राज फंड

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• SBI Mutual Fund launched its first Magnum Hybrid Long Short scheme under the Specialised Investment Fund (SIF) category.
• SBI म्यूचुअल फंड ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड) SIF) श्रेणी के तहत अपनी पहली मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट योजना लॉन्च की है।
• The scheme aims to generate regular income through derivatives strategies, including covered calls, arbitrage, and cash & derivatives segments.
• यह योजना डेरिवेटिव रणनीतियों जैसे कवर कॉल्स, आर्बिट्राज, और नकद व डेरिवेटिव सेगमेंट्स में निवेश करके नियमित आय उत्पन्न करना लक्ष्य करती है।
• Investment allocation: 65–75% equity, 25–35% debt, and 10% in REITs & InVITs; target returns are 8–11% (not guaranteed).
• निवेश आवंटन :65–75% इक्विटी, 25–35% डेट, और 10% REITs व InVITs; लक्षित रिटर्न 8–11% है) गारंटीकृत नहीं(।
• The New Fund Offer (NFO) opened for subscription from October 1, 2025.
• नया फंड ऑफर) NFO) 1 अक्टूबर 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला।

Ques: Which public sector bank became the second PSB to be approved as a Trading-Cum-Clearing Member (TCM) on the India International Bullion Exchange (IIBX)?
कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारत अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज)IIBX) पर ट्रेडिंग-) क्लियरिंग सदस्य-कमTCM) के रूप में अनुमोदित होने वाला दूसरा PSB बन गया?

A. Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
B. Indian Bank / इंडियन बैंक
C. Canara Bank / केनरा बैंक
D. Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
E. Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

• Bank of Baroda (BOB) has been approved by the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) to operate as a Trading-Cum-Clearing Member (TCM) on the India International Bullion Exchange (IIBX) at GIFT City, Gujarat.
• बैंक ऑफ बड़ौदा)BOB) को IFSCA द्वारा GIFT सिटी, गुजरात में India International Bullion Exchange (IIBX) पर ट्रेडिंग) क्लियरिंग सदस्य-कम-TCM) के रूप में संचालन की अनुमति दी गई है।
• BOB becomes the second Public Sector Bank (PSB) after SBI to receive the TCM status.
• BOB SBI के बाद दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है जिसे TCM का दर्जा मिला।
• IIBX, established by the Government of India in July 2022 at Gandhinagar, Gujarat, is India's first international bullion exchange.
• IIBX, जिसे भारत सरकार ने जुलाई 2022 में गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है।

Ques: BRICS-backed New Development Bank (NDB) will issue its first rupee-denominated bond in India before which year?
ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक)NDB) भारत में अपना पहला रुपए मूल्यवर्गित बॉन्ड किस वर्ष से पहले जारी करेगा?

A. 2024
B. 2025
C. 2026
D. 2027
E. 2028

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• The BRICS-backed New Development Bank (NDB) will issue its first rupee-denominated bond in India’s domestic market before end-March 2026.
• ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक)NDB) भारत के घरेलू बाजार में मार्च 2026 से पहले अपना पहला रुपए मूल्यवर्गित बॉन्ड जारी करेगा।
• Earlier, NDB raised funds in Chinese yuan and South African rand and is in advanced discussions with the RBI for this debut issuance.
• इससे पहले NDB ने चीनी युआन और दक्षिण अफ्रीकी रैंड में फंड जुटाए थे और यह पहली रुपए निर्गम के लिए RBI के साथ उन्नत चरण की बातचीत में है।
• The bank plans to raise $400–500 million via 3–5 year bonds in the first tranche.
• बैंक पहली किस्त में $400–500 मिलियन को 3–5 साल के बॉन्ड्स के जरिए जुटाने का लक्ष्य रखता है।

Ques: The Central Consumer Protection Authority (CCPA) recently imposed a penalty of ₹2,00,000 on which company for false and misleading price representations?
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने हाल ही में झूठे और भ्रामक मूल्य प्रस्तुतिकरण के लिए किस कंपनी पर ₹2,00,000 का जुर्माना लगाया है?

A. Amazon / अमेज़न
B. Flipkart / फ्लिपकार्ट
C. FirstCry (Digital Age Retail Pvt. Ltd.) / फर्स्टक्राई (डिजिटल एज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड)
D. Snapdeal / स्नैपडील
E. Myntra / मिंत्रा

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The CCPA has imposed a penalty of ₹2,00,000 on M/s Digital Age Retail Pvt. Ltd. (FirstCry) for misleading price representations.
- CCPA ने M/s Digital Age Retail Pvt. Ltd. (FirstCry) पर भ्रामक मूल्य प्रस्तुतिकरण के लिए ₹2,00,000 का जुर्माना लगाया है।
- The order was passed under Sections 10, 20, and 21 of the Consumer Protection Act, 2019.
- यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10, 20 और 21 के तहत पारित किया गया।
- The company displayed products as “MRP inclusive of all taxes,” but later levied extra GST at checkout, amounting to deceptive pricing.
- कंपनी ने उत्पादों पर “एमआरपी सभी करों सहित” दिखाया, लेकिन चेकआउट पर अतिरिक्त जीएसटी लगाया, जो भ्रामक मूल्य निर्धारण माना गया।
- This was held as misleading advertisement [Section 2(28)] and unfair trade practice [Section 2(47)] under the Act.
- इसे अधिनियम की धारा 2(28) (भ्रामक विज्ञापन) और धारा 2(47) (अनुचित व्यापार प्रथा) माना गया।
- By engaging in “drip pricing”, a dark pattern under the Dark Patterns Guidelines, 2023, consumers were misled about the final price.
- कंपनी ने “ड्रिप प्राइसिंग” अपनाई, जिसे डार्क पैटर्न गाइडलाइन्स, 2023 के तहत उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला माना गया।
- This also violated Rule 7(1)(e) of the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020, requiring total price inclusive of taxes to be shown upfront.
- यह ई-कॉमर्स नियम, 2020 के नियम 7(1)(e) का उल्लंघन था, जिसमें कुल मूल्य (सभी करों सहित) अग्रिम रूप से दिखाना आवश्यक है।

Ques: Which regulator barred HDFC Bank’s DIFC branch from taking new clients?
एचडीएफसी बैंक की DIFC शाखा को नए ग्राहक लेने से किस नियामक ने रोका?

A. DFSA | दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी

B. SEBI | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
C. RBI | भारतीय रिज़र्व बैंक
D. IMF | अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
E. FATF | वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

• The Dubai Financial Services Authority (DFSA) has barred HDFC Bank's DIFC branch from soliciting or conducting business with new clients, effective 26 September 2025.
• दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी)DFSA) ने एचडीएफसी बैंक की DIFC शाखा को 26 सितंबर 2025 से नए ग्राहकों के साथ कारोबार करने से रोका।
• The restriction covers all financial services, including advising on financial products, arranging investments, arranging credit, custody services, and client onboarding.
• यह रोक सभी वित्तीय सेवाओं पर लागू है – जैसे वित्तीय उत्पादों पर सलाह, निवेश सौदे तय करना, ऋण की व्यवस्था करना, कस्टडी सेवाएं और ग्राहकों का ऑनबोर्डिंग।
• HDFC Bank opened its DIFC branch on 4 August 2014 to provide wealth management services to the Indian diaspora in the Gulf.
• एचडीएफसी बैंक ने अपनी DIFC शाखा 4 अगस्त 2014 को खोली थी ताकि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासी समुदाय को वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान की जा सकें।
• This was HDFC Bank's third overseas branch, after Bahrain and Hong Kong.
• यह एचडीएफसी बैंक की तीसरी विदेशी शाखा थी, बहरीन और हांगकांग के बाद।

Genius

Ques: Which bank signed an MoU with Tata Power Renewable Energy Limited to provide financial support for solar energy adoption by MSMEs and C&I customers?
किस बैंक ने MSME और C&I ग्राहकों के लिए सौर ऊर्जा अपनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए Tata Power Renewable Energy Limited के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए?

A. State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
B. Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

C. ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
D. Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
E. HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

• Bank of Baroda (BOB) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL) to support MSMEs and Commercial & Industrial (C&I) customers in adopting solar energy.
• बैंक ऑफ बड़ौदा)BOB) ने Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL) के साथ MSME और C&I ग्राहकों के लिए सौर ऊर्जा अपनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए।
• Under the MoU, BOB will offer loans for solar projects with interest rates starting from 7.75% for capacities up to 10 MW, through TPREL or its authorized partners.
• MoU के तहत, BOB 10 मेगावॉट तक क्षमता वाले सौर परियोजनाओं के लिए 7.75% से शुरू होने वाली ब्याज दर पर ऋण TPREL या उसके अधिकृत साझेदारों के माध्यम से प्रदान करेगा।
• The bank provides collateral-free loans up to ₹10 crore, covered under Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), with flexible repayment tenure up to 120 months, relaxed margin requirements starting at 20%, and concessional processing fees.
• बैंक ₹10 करोड़ तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण, CGTMSE के तहत कवर, 120 महीने तक लचीला पुनर्भुगतान अवधि, 20% से शुरू होने वाली आसान मार्जिन आवश्यकताएं, और सुपरिशुल्क में रियायत . प्रदान करेगा।

Ques: Which digital payments platform, in collaboration with Mastercard, launched the exclusive 'Tap & Pay' feature for Mastercard cardholders in India?
भारत में मास्टरकार्ड धारकों के लिए एक्सक्लूसिव 'टैप एंड पे' फीचर लॉन्च करने वाला डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है, जो मास्टरकार्ड के साथ सहयोग में है?

A. Paytm / पेटीएम
B. Google Pay / गूगल पे
C. PhonePe / फोनपे
D. Amazon Pay / अमेज़न पे
E. BharatPe / भारतपे

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• PhonePe Private Limited, a leading digital payments platform, in collaboration with Mastercard Inc., launched an exclusive 'Tap & Pay' feature for Mastercard cardholders in India.
• फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, ने मास्टरकार्ड इंक के सहयोग से भारत में मास्टरकार्ड धारकों के लिए 'टैप एंड पे' फीचर लॉन्च किया।
• Objective: To provide secure and frictionless 'tap and pay' experiences at physical retail outlets and support tokenised e-commerce transactions.
• उद्देश्यभौतिक रिटेल आउटलेट्स पर सुरक्षित और निर्बाध : 'टैप एंड पे' अनुभव प्रदान करना और टोकनाइज्ड ईकॉमर्स लेनदेन का समर्थन करना।-
• Eligible Users: Mastercard credit, debit, and prepaid cardholders in India.
• पात्र उपयोगकर्ता: भारत में मास्टरकार्ड क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड धारक।

About PhonePe:

- Established : 2015
- HQ : Bengaluru, Karnataka
- CEO : Sameer Nigam

Ques: Which body currently selects Non-Official Directors (NODs) for Public Sector Banks (PSBs)?
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों)PSBs) के लिए वर्तमान में गैर) आधिकारिक निदेशकों-NODs) का चयन कौन करता है?

A. Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
B. Ministry of Finance (Department of Financial Services) / वित्त मंत्रालय वित्तीय) (सेवाएं विभाग
C. Boards of PSBs / पीएसबी के बोर्ड
D. P J Nayak Committee / पी जे नायक समिति
E. SEBI / सेबी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• The Central Government has retained control over the appointment of Non-Official Directors (NODs) in Public Sector Banks (PSBs) to ensure consistent oversight and effective implementation of financial inclusion schemes.
• केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों)PSBs) में गैर) आधिकारिक निदेशकों-NODs) की नियुक्ति पर नियंत्रण बनाए रखा है ताकि निरंतर निगरानी और वित्तीय समावेशन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
• During PSB Manthan 2025, experts suggested that PSB boards should get this power, but the Govt rejected it.
• PSB मंथन 2025 के दौरान विशेषज्ञों ने यह शक्ति बोर्ड को देने का सुझाव दिया, लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया।
• In 2014, the P J Nayak Committee (RBI-appointed) had also recommended that PSB boards should appoint NODs, but this was not implemented.
• 2014 में आरबीआई द्वारा नियुक्त पीनायक समिति .जे. ने भी सिफारिश की थी कि PSB बोर्ड NODs नियुक्त करें, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।
• Currently, the Department of Financial Services (Finance Ministry) selects NODs for PSBs.
• वर्तमान में वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवाएं विभाग PSBs के लिए NODs का चयन करता है।
• Non-board directors in PSBs include Govt-nominated, RBI-nominated, Independent, and Shareholder-elected directors.
• PSBs में गैरबोर्ड निदेशकों में- सरकारनामित-, RBI-नामित, स्वतंत्र, और शेयरधारकों द्वारा

चुने गए निदेशक शामिल होते हैं।

Ques: Who has been appointed as the new Deputy Governor of the Reserve Bank of India (RBI) effective from October 9, 2025?
9 अक्टूबर 2025 से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नए उप-गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A. Rajeshwar Rao / राजेश्वर राव
B. Poonam Gupta / पूनम गुप्ता
C. Swaminathan Janakiraman / स्वामीनाथन जनकीरामन
D. T. Rabi Sankar / टी. रबी शंकर
E. Shirish Chandhra Murmu / शिरीष चंद्र मुरमु

Answer : Option E

Explanation / व्याख्या:

• The Appointments Committee of the Cabinet approved the appointment of Shirish Chandhra Murmu as the Deputy Governor of RBI for a three-year term effective October 9, 2025.
• मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने शिरीष चंद्र मुरमु को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का उप-गवर्नर तीन वर्ष की अवधि के लिए 9 अक्टूबर 2025 से नियुक्त किया है।
• He will succeed Rajeshwar Rao, whose extended term as Deputy Governor ends on October 8, 2025.
• वे राजेश्वर राव के उत्तराधिकारी होंगे, जिनका विस्तारित कार्यकाल 8 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगा।
• Currently, Murmu is serving as Executive Director (ED), Department of Supervision, RBI.
• वर्तमान में मुरमु कार्यकारी निदेशक (ED), पर्यवेक्षण विभाग, RBI के रूप में कार्यरत हैं।
• RBI has four deputy governors: T. Rabi Sankar, Swaminathan Janakiraman, Poonam Gupta, and now Shirish Chandhra Murmu.
• RBI में कुल चार उप-गवर्नर होते हैं: टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जनकीरामन, पूनम गुप्ता और अब शिरीष चंद्र मुरमु।
• As per the RBI Act, 1934, RBI must have four Deputy Governors – two from within RBI, one from the commercial banking sector, and one economist to

head the Monetary Policy Department.
• RBI अधिनियम, 1934 के अनुसार RBI में चार उप-गवर्नर होना अनिवार्य है – दो RBI से, एक वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से और एक अर्थशास्त्री जो मौद्रिक नीति विभाग का नेतृत्व करता है।

Ques: RBI is likely to allow which company's exit from the Upper Layer NBFC classification?
RBI किस कंपनी को अपर लेयर NBFC वर्गीकरण से बाहर निकलने की अनुमति देने जा रहा है?

A. Reliance Capital / रिलायंस कैपिटल
B. Shriram Finance / श्रीराम फाइनेंस
C. Tata Sons / टाटा सन्स
D. Bajaj Finance / बजाज फाइनेंस
E. HDFC Ltd / एचडीएफसी लिमिटेड

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• The RBI had classified Tata Sons as an Upper Layer NBFC in September 2022, mandating that it list by 30 September 2025.
• RBI ने सितंबर 2022 में टाटा सन्स को अपर लेयर NBFC में रखा था और उन्हें 30 सितंबर 2025 तक लिस्टिंग करने का निर्देश दिया था।
• In March 2024, Tata Sons requested de-registration to avoid listing, and RBI is now considering approval subject to certain conditions.
• मार्च 2024 में टाटा सन्स ने लिस्टिंग से बचने के लिए डिरजिस्ट्रेशन का अनुरो-ध किया था, और RBI अब इसे शर्तों के साथ मंजूरी देने पर विचार कर रहा है।
• Shapoorji Pallonji Group (holding 18% stake) sought a fair exit route, while Tata Trusts, the major stakeholder, wants Tata Sons to remain unlisted.
• शापूरजी पालोनजी ग्रुप)18% हिस्सेदारीने न्यायसंगत एग्जिट रूट मांगा है (, जबकि टाटा ट्रस्ट मुख्य हिस्सेदार के रूप में चाहता है कि टाटा सन्स अनलिस्टेड रहे।
• The decision will balance financial stability, investor exit, and regulatory compliance.
• यह निर्णय वित्तीय स्थिरता, निवेशक एग्जिट और रेगुलेटरी अनुपालन के बीच संतुलन बनाएगा।

Ques: Which company has been barred by SEBI and fined along with its three senior executives for alleged financial misstatement?
किस कंपनी को सेबी ने कथित वित्तीय गड़बड़ी के लिए तीन वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रतिबंधित और दंडित किया है?

A. Man Industries (India) Ltd. / मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इंडिया)
B. Adani Enterprises / अडाणी एंटरप्राइजेज
C. Reliance Power / रिलायंस पावर
D. L&T Finance / एल एंड टी फाइनेंस
E. Hindustan Zinc / हिंदुस्तान जिंक

Answer :Option A

Explanation / व्याख्या:

• SEBI (Securities and Exchange Board of India) barred Man Industries (India) Ltd. and three of its senior executives from accessing the securities market for two years.
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)SEBI) ने मैन इंडस्ट्रीजलिमिटेड (इंडिया) और इसके तीन वरिष्ठ अधिकारियों को दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया।
• A monetary penalty of ₹25 lakh each was imposed for alleged financial misstatements.
• प्रत्येक पर ₹25 लाख का जुर्माना लगाया गया, जो कथित वित्तीय गड़बड़ी से संबंधित है।
• This action was taken to ensure corporate governance and investor protection
• यह कार्रवाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस और निवेशक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए की गई।

Penalised executives include / दंडित अधिकारियों में शामिल हैं:

- Ramesh Mansukhani – Chairman / रमेश मंसुखानी – चेयरमैन
- Nikhil Mansukhani – Executive Director / निखिल मंसुखानी – एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
- Ashok Gupta – Former Executive Director & Current CFO / अशोक गुप्ता – पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं वर्तमान CFO

Ques: The Reserve Bank of India imposed a monetary penalty of ₹2.7 lakh on which company for non-compliance with norms related to 'Internal Ombudsman'?
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'आंतरिक लोकपाल' से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर ₹2.7 लाख का जुर्माना किस कंपनी पर लगाया?

A. Manappuram Finance Limited / मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड
B. Mahindra Finance / महिंद्रा फाइनेंस
C. Bajaj Finance Limited / बजाज फाइनेंस लिमिटेड
D. Shriram Finance Limited / श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड
E. Muthoot FinCorp Limited / मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड

Answer : Option E

Explanation / व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) imposed a monetary penalty of ₹2.7 lakh on Muthoot FinCorp Limited for non-compliance with Internal Ombudsman guidelines.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आंतरिक लोकपाल दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड पर ₹2.7 लाख का मौद्रिक दंड लगाया।
• RBI found that the company failed to establish an auto-escalation system of complaints rejected partly or wholly by its grievance redress mechanism to the Internal Ombudsman.
• RBI ने पाया कि कंपनी अपने शिकायत निवारण तंत्र द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत शिकायतों को आंतरिक लोकपाल तक स्वतः अग्रेषित करने की प्रणाली स्थापित करने में विफल रही।
• The penalty was imposed under Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the RBI Act, 1934.
• यह दंड RBI अधिनियम, 1934 की धारा 58G(1)(b) तथा 58B(5)(aa) के तहत लगाया गया।

Ques: Which two institutions have partnered to co-lend gold loans targeting semi-urban and rural customers?
किस दो संस्थानों ने अर्ध-शहरी और ग्रामीण ग्राहकों को लक्षित करते हुए गोल्ड लोन सह-वित्तपोषण के लिए साझेदारी की है?

A. SBI and Bajaj Finance / एसबीआई और बजाज फाइनेंस
B. Bank of Baroda and IIFL Finance / बैंक ऑफ बड़ौदा और IIFL फाइनेंस
C. HDFC Bank and Muthoot Finance / एचडीएफसी बैंक और मुथूट फाइनेंस
D. Axis Bank and Manappuram Finance / एक्सिस बैंक और मनप्पुरम फाइनेंस
E. PNB and Shriram Finance / पीएनबी और श्रीराम फाइनेंस

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• Bank of Baroda and IIFL Finance have partnered to co-lend gold loans, targeting semi-urban and rural customers.
• बैंक ऑफ बड़ौदा और IIFL फाइनेंस ने अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को लक्षित करते हुए गोल्ड लोन सहवित्तपोषण- के लिए साझेदारी की है।
• The scheme primarily focuses on underserved and unbanked customers.
• यह योजना मुख्य रूप से अविकसित और बिना बैंक सुविधा वाले ग्राहकों को लक्षित करेगी।
• The objective is to provide fast, easy, and affordable credit, especially for agricultural and allied activities.
• उद्देश्य है छोटे उधारकर्ताओं को तेज़, आसान और किफायती ऋण उपलब्ध कराना, विशेषकर कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए।
• This initiative will enhance financial inclusion and bring more rural customers into the formal credit system.
• इस पहल से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और अधिक ग्रामीण ग्राहक औपचारिक ऋण प्रणाली में जुड़ेंगे।

Ques: From which date will the RBI's new rules on interest rates, gold loans, and exposure norms come into effect?
आरबीआई के ब्याज दर, सोना ऋण और जोखिम मानकों पर नए नियम किस तारीख से प्रभावी होंगे?

A. September 15
B. October 1
C. November 1
D. December 31
E. January 1

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) announced sweeping regulatory changes effective from October 1, 2025.
• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले बड़े बदलावों की घोषणा की।

Key changes include:

– Banks can reduce spread components on advances earlier than the 3-year lock-in period, benefiting borrowers or allowing switch to fixed rates.
– ऋण पर ब्याज दर में ढील बैंकों को :3 साल की लॉक इन अवधि-से पहले स्प्रेड घटाने की अनुमति, जिससे उधारकर्ताओं को लाभ और फिक्स्ड रेट पर स्विच करने का विकल्प।
– Working capital loans against gold/silver for manufacturers and Tier-3/Tier-4 banks.
– सोनाचांदी का उप/उत्पादन में सोने :चांदी के विरुद्ध वर्किंग कैपिटल ऋण/योग करने वाले उधारकर्ताओं के लिए, टियर-3/टियर-4 बैंक भी ऐसे ऋण दे सकते हैं।
– Revised limits for foreign currency and rupee-denominated debt instruments.
– विदेशी मुद्रा और रुपये में ऋण साधनों के लिए संशोधित सीमा।
– Exposure of Indian branches of foreign banks to their HO & subsidiaries to be reckoned only under Large Exposure Framework (LEF), not Intra-group Transactions (ITE).
– विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं का अपने मुख्यालय और सहायक कंपनियों के प्रति जोखिम केवल बड़े एक्सपोज़र ढांचे)LEF) में गिना जाएगा, ITE में नहीं।

• These measures aim to enhance financial flexibility, inclusion, and transparency in India’s banking system.
• ये बदलाव भारत के बैंकिंग सिस्टम में वित्तीय लचीलापन, समावेशन और पारदर्शिता बढ़ाने का उद्देश्य रखते हैं।

Ques: Who have been recently appointed as the Managing Directors (MD) & Chief Executive Officers (CEO) of Union Bank of India ?
हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कौन नियुक्त किए गए हैं?

A. Asheesh Pandey / आशीष पांडे
B. A. Manimekalai / ए. मणिमेकलै
C. Rajeev Pandey / राजीव पांडे
D. Kalyan Kumar / कल्याण कुमार
E. Rajesh Kumar / राजेश कुमार

Answer : Option A

Explanation / व्याख्या:

• Asheesh Pandey, Executive Director of Bank of Maharashtra, has been appointed as MD & CEO of Union Bank of India (UBI) for a three-year tenure, replacing A. Manimekalai.
• अशीष पांडे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक, को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) का MD & CEO तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। वे ए. मनीमेकलाई का स्थान ले रहे हैं।
• Kalyan Kumar, Executive Director of Punjab National Bank (PNB), has been appointed as MD & CEO of Central Bank of India (CBI) for a three-year tenure, replacing Matam Venkata Rao.
• कल्याण कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक, को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) का MD & CEO तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। वे मातम वेंकट राव का स्थान ले रहे हैं।

Ques: Which organisation launched 'Ideabaaz', India's first integrated marketplace for start-ups and investors?
भारत का पहला एकीकृत मंच 'आइडियाबाज़', जो स्टार्टअप्स और निवेशकों को जोड़ता है-, किस संगठन ने लॉन्च किया?

A) SEBI / सेबी
B) BSE / बीएसई
C) NSE / एनएसई
D) SIDBI / सिडबी
E) Invest India / इन्वेस्ट इंडिया

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• The National Stock Exchange (NSE) launched Ideabaaz, India's first integrated marketplace connecting start-ups with investors.
• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया)NSE) ने आइडियाबाज़ लॉन्च किया, जो देश का पहला एकीकृत मंच है जहाँ स्टार्टअप्स और निवेशकों को जोड़ा जाएगा।-
• The platform aims to nurture India's entrepreneurial spirit and support start-ups in growing into listed companies.
• यह मंच भारत की उद्यमिता भावना को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को- सूचीबद्ध कंपनियों में विकसित करने में मदद करेगा।
• NSE MD & CEO Ashishkumar Chauhan stated that Ideabaaz will empower start-ups and accelerate India's growth journey.
• NSE के प्रबंध निदेशक एवं CEO अशिषकुमार चौहान ने कहा कि आइडियाबाज़ स्टार्ट-अप्स को सशक्त बनाकर भारत की विकास यात्रा को गति देगा।
• Mudith Kumar, Co-Founder & COO, emphasized that the platform is creating an inclusive, transparent, and future-ready ecosystem.
• मुदित कुमार, सह संस्थापक एवं-COO, ने कहा कि यह मंच समावेशी, पारदर्शी और भविष्यउन्मुख- इकोसिस्टम बना रहा है।

Ques: Moody's has affirmed India's long-term local and foreign-currency issuer ratings at which level?
मूडीज़ ने भारत की दीर्घकालिक स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग किस स्तर पर बरकरार रखी है?

A. BBB+
B. BBB
C. Baa3
D. A2
E. P-3

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

• Moody's Ratings has affirmed India's long-term local and foreign-currency issuer ratings and the local-currency senior unsecured rating at Baa3.
• मूडीज़ रेटिंग्स ने भारत सरकार की दीर्घकालिक स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग और स्थानीय मुद्रा सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग को Baa3 पर बरकरार रखा।
• India's short-term local-currency rating is affirmed at P-3.
• भारत की अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग P-3 पर बरकरार रखी गई है।
• The stable outlook reflects India's credit strengths, including a large, fast-growing economy, sound external position, and resilient domestic financing base.
• स्थिर दृष्टिकोण भारत की क्रेडिट ताकतों को दर्शाता है, जिसमें बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत बाहरी स्थिति, और लचीला घरेलू वित्तपोषण आधार शामिल है।
• Challenges remain due to high debt burden, fiscal weaknesses, and external risks such as US tariffs and global policy measures.
• चुनौतियां बनी हुई हैं जैसे उच्च ऋण बोझ, राजकोषीय कमजोरियां और अमेरिकी टैरिफ एवं वैश्विक नीतिगत उपाय जैसी बाहरी जोखिम।
• India's long-term local-currency bond ceiling remains unchanged at A2.
• भारत की दीर्घकालिक स्थानीय मुद्रा बांड सीमा A2 पर अपरिवर्तित रही